

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:—श्री बी०एल०मेहरड़ा, आर०ए०एस०)

अपील संख्या:—241/2016/223 (2016/00241)

1. किशनलाल दत्तक पुत्र बिहारी, जाति रैगर, निवासी ग्राम हरमाड़ा, तह० रूपनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांत

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोंडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध विरुद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ दिनांक 18.5.2016 अंतर्गत वाद संख्या 08/2016.

उपस्थित:—

1. श्री मंगलाराम चौधरी, वकील अपीलांत ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1 .

निर्णय

दिनांक:— 5.7.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.5.2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलांत ने अधी०न्याया० में वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज०काश्त०अधि० के तहत पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खाता संख्या 590/517 के खसरा नंबर 994/3 रकबा 9-18-10 ग्राम हरमाड़ा में स्थित है । विवादित भूमि वादी के दत्तक पिता बिहारी को दिनांक 26.11.1975 को आवंटन की गई एवं आवंटन के बाद से आवंटी बिहारी मौके पर काबिज रहा एवं उसका स्वर्गवास दिनांक 14.2.1986 को हो जाने के पश्चात् वादी उसका दत्तक पुत्र होकर मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि अपीलांत के नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा दर्ज नहीं करने के कारण वादी को यह वाद प्रस्तुत पड़ा है । अतः वाद वादी स्वीकार कर विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी०न्याया० ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.5.2016 द्वारा

वादी/अपीलांट का वाद खारिज कर दिया । अधी०न्याया० के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों को तलब किया गया । रेस्पों के उपस्थित होने तथा अधी०न्याया० का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी०न्याया० ने अपीलांट को बिना विधिवत् नोटिस दिये एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना सरसरी तौर पर एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय प्रदान किया है जो न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी०न्याया० ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि वाद वादी की साक्ष्य हेतु नियत था जिसमें वादी की साक्ष्य होनी थी किन्तु अधी०न्याया० ने वादी की साक्ष्य लिये बिना ही उपरोक्त प्रकरण को लोक अदालत कैम्प हरमाड़ा में नियत कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निरस्त कर दिया । बहस में आगे कथन किया कि वादी/अपीलांट विवादित आराजी के खातेदार होकर मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है । यह भूमि वादी के दत्तक पिता बिहारी को दिनांक 26.11.1975 को आवंटन की गई थी । अधी०न्याया० ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उपखण्ड अधिकारी ने प्रस्तुत प्रकरण में आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं करना मानकर नियम 14 (4) आवंटन नियम 1970 के तहत प्रकरण बनाकर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को नहीं है । आवंटन निरस्तीकरण के प्रावधान भू-राजस्व अधी० के तहत किया जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर विद्वान अधी०न्याया० का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।
5. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी०न्याया० ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण कर विधिसम्मत रूप से निर्णय व डिक्री पारित की है। वादी ने अधी०न्याया० के समक्ष गोद पुत्र के आधार पर वाद पेश किया है किन्तु गोदनामे के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया । अधी०न्याया० का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।
6. हमने उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी०न्याया० ने प्रकरण को कैम्प कोर्ट हरमाड़ा में रखकर अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निर्णित किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी०न्याया० के समक्ष वाद वादी की साक्ष्य में नियत था किन्तु अधी०न्याया० ने वादी की साक्ष्य लिये बिना प्रकरण को कैम्प में बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये निर्णित किया है जिसे विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी०न्याया० ने प्रकरण को सरसरी तौर पर निर्णित किया है जबकि अधी०न्याया० को वाद में आवश्यक तनकियात कायम कर प्रकरण में तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिये । ऐसी स्थिति में अधी०न्याया० द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है ।
7. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी०न्याया० का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी०न्याया० को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.5.2016 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीन न्याया को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वाद में वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर, उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी०एल०मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 5.7.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी०एल०मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर